

क्रमांक:- 1589



शरणा : - 1- 10/83/94 प0

2- 10/83/94 बी

विषय :- राजस्थान आवासन मंडल द्वारा सार्वजनिक  
प्रयोजनाय आवासीय कालोनी बनाने हेतु आप्त  
का आर्थिक आर्ट ग्राम रजोपुर, बंबाला तहसील  
सुंगानेर जिला जयपुर रजोपुर वाद सीमा 10/83  
94 प0 रकबा 5 बीघा 10 बिस्वा, 10/83/94  
बी रकबा 4 बीघा 19 बिस्वा कुल भूमि  
10 बीघा 09 बिस्वा ।

पीठकीन अधिकारी :- 1- श्री बी०एम० शर्मा, विशेषाधिकारी, नगरीय  
विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।

पक्षकारान् :

2- श्रीया, पांच्या पुत्र रामदेव ।

3- श्री रामनाथ पुत्र महादेव ।

3- राजस्थान आवासन मंडल जयपुर जस्ये श्री  
रजिस्ट्रार जी०सी० गंग, पडवोकेट एवं भूमि आप्त  
अधिकारी श्री आर०के० पारीक एवं श्री सत्येन्द्र  
शर्मा

1- राज्य सरकार के नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान  
जयपुर की ओर से राजस्थान आवासन मंडल के सार्वजनिक प्रयोजनाय अर्थात्  
आवासीय कालोनी बनाने हेतु ग्राम रजोपुर, बंबाला जिला जयपुर की कुल  
1213 बीघा 17 बिस्वा भूमि आप्त करने के आदेश राजस्थान भूमि  
आप्त अधिनियम 1953 जिसे आगे अधिनियम शब्द से सम्बोधित किया  
जायेगा की धारा 4 के अन्तर्गत दिये गये अधिसूचना क्रमांक प०७३/३/सीआन,  
111/83 दिनांक 22-8-83 को जारी की गई जो राजस्थान राजपत्र में  
दिनांक 22-8-83 को प्रकाशित की गई ।

2- तत्पश्चात् राज्य सरकार ने भूमि को आप्त की अतिआवश्यकता  
को ध्यान में रखते हुए राजस्थान भूमि आप्त अधिनियम 1953 की  
17 की उपधारा 4 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में धारा 9 की  
उपधारा 11 में उल्लेखित नोटिस प्रकाशित हो जाने की तिथि से 15  
की समाप्ति पर उपरोक्त विज्ञापित में उल्लेखित भूमि का कब्जा लेने के  
विशेषाधिकारी, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान आवासन  
मंडल, जयपुर को विज्ञापित क्रमांक प०७३/२०/नविजो/111/83 दिनांक  
19-मार्च, 1984 जो राजस्थान राजपत्र के भाग 11 में प्रकाशित

विशेषाधिकारी

नगरीय विकास एवं आवासन विभाग,  
राजस्थान, जयपुर



जो राजस्थान राजस्व के भाग 1 [ख] में दिनांक 19 मार्च, 1984 को प्रकाशित हुये के द्वारा अधिस्त किया।

3- धारा 17 [4] की अधिस्तना प्रकाशित होने के पश्चात् नियमानुसार सम्बन्धित भूमि का कब्जा प्राप्त करने हेतु अधिनियम की धारा 9 [1] को नोटिस दिनांक 23-5-84 को जारी किया गया। उक्त नोटिस जारी होने के पश्चात् 15 दिवस पश्चात् भूमि का कब्जा प्राप्त करने हेतु कार्यवाही की गई जिसके अनुसार दिनांक 11-6-86 को कुल 1173 बीघा 16 बिस्वा भूमि का कब्जा लिया गया। शेष भूमि का कब्जा स्थगन आदेशों के कारण नहीं लिया गया। उक्त 1173 बीघा 16 बिस्वा भूमि का कब्जा लेकर मोके पर ही राजस्थान आवासन मण्डल के प्रतिनिधि को सम्मन्त्राया गया।

4- उपरोक्त कार्यवाही के पश्चात् सम्बन्धित आदेशों को अधिनियम की धारा 9 [3] के अन्तर्गत नोटिस जारी किये जाकर सम्बन्धित खसरा नम्बरों की भूमि का क्लेम प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया।

5- वर्तमान में उपरोक्त में से कुल 10 बीघा 09 बिस्वा भूमि का ही काट्ट दिया जा रहा है। काट्ट दिये जाने वाली भूमि का विवरण निम्न प्रकार है :-

| क्र.सं. | वाद लब्ध्या    | नाम आतेदार                                    | खसरा नं०                                                    | भूमि का क्षेत्र                                                    |
|---------|----------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|         |                |                                               |                                                             | बीघा बिस्वा                                                        |
| 1-      | 10/83[94 प०]   | श्री श्रीया, पाँच्या पुत्र<br>महादेव रामदेव । | 367<br>369<br>370<br>371<br>372<br>374<br>375<br>376<br>381 | 0 10<br>0 09<br>0 0<br>1 03<br>0 06<br>0 15<br>0 19<br>0 17<br>0 1 |
|         |                |                                               |                                                             | 5                                                                  |
| 2       | 10/83[94 बीघा] | श्री रामनाथ पुत्र<br>महादेव ।                 | 57<br>78<br>260<br>643                                      | 0 13<br>3 04<br>1 02<br>4 19                                       |
|         |                |                                               |                                                             | कुल भूमि 10 09                                                     |

उपरोक्त भूमि राजस्व रिकार्ड के उपरोक्त आतेदारों के नाम दर्ज है, जो

श्री श्रीया, पाँच्या पुत्र  
महादेव रामदेव ।  
जयपुर





का: समुचित आंकड़ा दिया जा रहा है।

6- अधिनियम की धारा 9 [3] के अन्तर्गत अधिसूचनाओं के नोटिफिकेशन किया गया जिसके उत्तर में उनके द्वारा कोम प्रस्तुत किया गया जिसका विवरण निम्न प्रकार है :-

[1] याचक [क्रिया 10/83/94 पृष्ठ] की शीघा, पाँचवा पुन रावेज द्वारा प्रस्तुत कोम :-

1- यह कि उपरोक्त उत्तरा नम्बरान में से उत्तरा No 367 में से 320 वर्ग मी. भूमि श्रीलाल व 306 वर्ग मी. भूमि लालराम को व 300 मी. प्राची शीघा उर्फ सिरिला उर्फ श्रीराम ने तहसील सांगानेर से हजाजत लेकर पुछता मकान बनाने के लिए दी है जिस पर दोनों ने अपना पुछता मकान बना दिया है। इस प्रकार इस 6 बिस्वा भूमि का मुआवजा लालराम व श्रीलाल व बाबुलाल को निम्न आधार पर दिलाया जावे।

2- यह कि प्राची उर्फ सिरिला उर्फ श्रीराम को 2 बीघा 9 बिस्वा का जोर उपरोक्त 947 वर्ग मी. का मुआवजा लालराम व श्रीलाल व बाबुलाल को व 2 बीघा 15 बिस्वा का मुआवजा पाँच प्राची को दिलाया जावे।

3- यह कि प्राचीगण की शीघा उर्फ सिरिला उर्फ श्रीराम व पाँच की उक्त भूमि नेशनल हाईवे दोक रोड पर स्थित है जो नगर परिषद् हरि में अरबन लेन्ड की भूमि है और सांगानेर नगरपालिका की सीमा से भी हुई है जो पूर्णतया विकसित व आवसीय क्षेत्र भूमि के सहारे स्थित है। इस कारण प्राचीगण की 5 बीघा 4 बिस्वा भूमि की बाजार दर 82 रुपया बीघा की कीमत की है। इस कारण इस भूमि का मुआवजा प्रकार दिलाया जावे।

[क] शीघा उर्फ सिरिला उर्फ श्रीराम प्राची को 2 बीघा 9 बिस्वा का 2,00,900 रुपये के दो लाख नौ सौ रुपये भूमि की कीमत के दिलाये जावे।

[ख] पाँच प्राची को 2 बीघा 15 बिस्वा का 2,25,500/- रुपये दिलाये जावे।

विशेषाधिकारी

नगरीय विकास एवं आवासन विभाग  
राजस्थान, जयपुर

यह कि श्रीलाल व लालराम, बाबुलाल प्राची शीघा के पुत्रान है और यह भूमि वैयक्तिक भूमि थी जिन्में से प्राची शीघा ने अपने तीनों लड़कों को अलग-अलग तहसील के नियमानुसार हजाजत लेकर भूमि अलग-2 से दे दी इस कारण श्रीलाल व लालराम, बाबुलाल को चूँकि भूमि आवसीय भूमि है व उसके उपर पुछता मकान बने हुए है इस कारण निम्न प्रकार से मुआवजा दिलाया जावे। क्योंकि वे हितधारी व्यक्ति है।

[क] यह कि श्रीलाल की आवसीय भूमि नेशनल हाईवे दोक रोड पर



स्थित होने से 300 रुपये प्रति वर्गगज के हिसाब से निम्न प्रकार दिलाई जावे :-

क- यह कि भूमि की कीमत के 320 वर्गगज के 300 रुपये प्रति वर्गगज के हिसाब से 96000 रुपये दिलाये जावे और मकानात पक्काता जो संलग्न नको में दिखाये है और जो तीन दुकानात के रूप में बने हुए हैं का मुआवजा 33496 रुपये दिलाया जावे । इस प्रकार श्रीलाल को कुल मुआवजा 1,29,496 रुपये दिलाये जावे ।

ख- यह कि लादुराम की आवासीय भूमि मेहनत हाथी चौक रोड पर स्थित होने से 300 रुपये प्रति गज के हिसाब से निम्न प्रकार दिलाई जावे :-

क- यह कि भूमि की कीमत के 306 वर्गगज के 300 रुपये प्रति वर्गगज के हिसाब से 91,800 रुपये दिलाये जावे ।

ख- यह कि दो कमरे, दो दुकान संलग्न नको में दिखाये है व एक हेन्ड-पम्प 120 फुट गहरा और इन कमरों में बिजली का फिटिंग व आटा पीसने की चक्की 10 हात्तावर की लगी हुई है जो चाबू हात्त में है के मुआवजे के मकानों के 29,202 रुपये हेन्डपम्प के 8000 रुपये और चक्की के 25000 रुपये व छप्पर बरण्डा के 3220 रुपया इस प्रकार कुल मुआवजा 1,57,222 रुपया लादुराम को दिलाया जावे ।

ग- यह कि बाबूलाल की आवासीय भूमि मेहनत हाथी चौक रोड पर स्थित होने से निम्न प्रकार दिलाई जावे :-

क- यह कि भूमि की कीमत के 320 वर्गगज भूमि के 300 रुपये प्रति वर्गगज के हिसाब से 36000 रुपये दिलाये जावे और दुकानात पक्काता तीन और एक कच्चा धर बने हुए हैं उनका मुआवजा 40000 रुपये दिलाया जावे । इस प्रकार बाबूलाल को 1,36,000/- रुपये दिलाया जावे ।

5- यह कि उपरोक्त भूमि में श्रीया उर्फ तिरिला उष श्रीराम व पाँच बेटों का पक्का कुआ चूना पत्थर का बना हुआ है और जिसमें बोरिंग हो रहा है और बिजली का पम्प रेट लगा हुआ है इसका निम्न प्रकार मुआवजा दोनों को बराबर दिलाया जावे :-

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| क- कुआ की कीमत           | रुपया 37,590.00 |
| ख- बोरिंग पम्पिंग सेट के | 34,380.00       |
| ग- पायपों की कीमत से     | 5,244.00        |
| घ- टाणा पक्का            | 5,000.00        |
| ङ- बिजली की मोटर         | 7,000.00        |
| च- स्टील केनल            | 3,120.00        |
| छ- सीमेन्ट पायल          | 950.00          |
| ज- समूची बिजली           | 500.00          |

विशेषाधिकारी  
जननीय विकास एवं भ्रष्टाचार विरोध  
राजस्थान, बयपुर





जोती है इस जंगल कापुर शहर के नजदीक व भालन बाड़ी पर स्थित।  
जोते से इस भूमि की काजार दर 8000 रुपये प्रति बीघा की है और  
इस प्रकार प्राप्ती को 4,09,900/- रुपये भूमि के मूल्य के रूप में क्षतिपूर्ति  
राशि दिलाई जावे।

2- यह कि इस भूमि में प्राप्ती में जंगल की सुरक्षा के लिए डीजी लगा  
रखी है और उस पर पानी डूबे लगे हुए हैं उसकी क्षति राशि के 5000/-  
रुपये दिलाई जावे।

3- यह कि इस भूमि में बम्बूल के 10 पेड़, लेजडा 6 पेड़, बेर के 2 पेड़ है  
उनकी क्षति राशि का रुपये 10,000/- दिलाये जावे।

4- यह कि प्राप्ती की तारीख 11-6-84 से जब तक क्षतिपूर्ति न मिले तब  
तक नियमानुसार 6 प्रतिशत क्षतिपूर्ति राशि पर दिलाई जावे।

5- यह कि प्राप्ती को अन्तिम रूप से स्वीकृत करने का क्षतिपूर्ति क्षति  
राशि पर 10 प्रतिशत दिलाई जावे।

6- यह कि प्राप्ती को मुकदमे के खर्च का क्षतिपूर्ति की राशि पर 5 प्रतिशत  
दिलाया जावे।

7- राजस्थान आवासन मण्डल ने दावेदारों के क्लेम का उत्तर प्रस्तुत  
कर क्लेम में मांगी गई क्षतिपूर्ति की राशि को अधिक बताते हुए अस्वीकार  
किया तथा यह बताया कि भूमि की कीमत अधिक से अधिक 10,000/-  
रुपये प्रति बीघा हो सकती है।

8- भूमि पर स्थित स्ट्रक्चर के सम्बन्ध में राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा  
निम्न प्रकार सूचित किया गया :-

1- वाद संख्या 10/82/94 ए0 श्रीया, पौड्या पृथ रामदेव :-

|                |       |          |
|----------------|-------|----------|
| 1- भेनारी बुवा | रुपये | 2776.85  |
| 2- बोरिंग      | रुपये | 9928.12  |
| 3- झमटी        | रुपये | 317.47   |
| 4- लेजडा       | रुपये | 10165.50 |
| 5- चकफ हट      | रुपये | 306.90   |
| 6- चकफ हट      | रुपये | 884.70   |
| 7- मेडवाल हट   | रुपये | 972.56   |
| कुल रुपये      |       | 25352.10 |

2- वाद संख्या 10/83/94 बी॥ श्री रामनाथ पृथमहादेव :-

राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा यह सूचित किया गया है कि कोई  
स्थायी स्ट्रक्चर नहीं है एवं न ही तकमीना पेश किया गया।

विशेषाधिकारी  
य विकास एवं आवासन विभाग  
राजस्थान, जयपुर





जाती है इस कारण जयपुर शहर के नजदीक व आसपास जो भूमि है उस पर जो भी भूखे भूमे से इस भूमि की बाजार दर 82000 रुपये प्रतिबिघा की दर और इस प्रकार प्राप्ती को 4,05,900/- रुपये भूमि के कीमत के रूप में क्षतिपूर्ति राशि दिलाई जावे ।

2- यह कि इस भूमि में प्राप्ती ने जमीन की सुरक्षा के लिए डीपी लगा रखी है और उस पर पानी कुवे लगे हुए हैं उसकी क्षति राशि के 5000/- रुपये दिलाई जावे ।

3- यह कि इस भूमि में बज्जल के 10 पेठ, खेजडा 6 पेठ, बेर के 2 पेठ है उनकी क्षति राशि का रुपये 10,000/- दिलाये जावे ।

4- यह कि प्राप्ती को तारीख 11-6-84 से जब तक क्षतिपूर्ति न मिले तब तक नियमानुसार 6 प्रतिशत क्षतिपूर्ति राशि पर दिलाई जावे ।

5- यह कि प्राप्ती को अनिवार्य रूप से अधिपत करने का क्षतिपूर्ति क्षति राशि पर 10 प्रतिशत दिलाई जावे ।

6- यह कि प्राप्ती को मुख्यों के बच्चों का क्षतिपूर्ति की राशि पर 5 प्रतिशत दिलाया जावे ।

7- राजस्थान आवासन मण्डल ने दावेदारों के केम का उत्तर प्रस्तुत कर केम में मांगी गई क्षतिपूर्ति की राशि को अधिक बताते हुए अस्वीकार किया तथा यह बताया कि भूमि की कीमत अधिक से अधिक 10,000/- रुपये प्रति बीघा हो सकती है ।

8- भूमि पर स्थित स्ट्रेकर्स के सम्बन्ध में राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा निम्न प्रकार सूचित किया गया :-

1- वाद संख्या 10/82/94 एओ श्रीया, पांच्या पुत्र रामदेव :-

|               |       |          |
|---------------|-------|----------|
| 1- भेसरी बुवा | रुपये | 2776.85  |
| 2- बौदिंग     | रुपये | 9928.12  |
| 3- समदी       | रुपये | 317.47   |
| 4- कण्ठपम     | रुपये | 10165.50 |
| 5- चकप हट     | रुपये | 306.90   |
| 6- चकप हट     | रुपये | 884.70   |
| 7- भुवान हट   | रुपये | 972.56   |
| कुल रुपये     |       | 25352.10 |

2- वाद संख्या 10/83/94 जी। श्री रामनाथ पुत्र महादेव :-

राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा यह सूचित किया गया है कि कोई स्थायी स्ट्रेकर नहीं है एवं न ही तकमीना पेश किया गया ।

विशेषाधिकारी  
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग  
राजस्थान, जयपुर



9] राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा अपने जवाब में तीन विक्रय पत्र क्रमांक: दिनांक 24 अक्टूबर, 1983, 19 मार्च, 1984 एवं 30-5-83 की प्रतियाँ पेश की गईं।

10] सम्बन्धित दावेदारों द्वारा निम्न प्रकार दस्तावेज अपने पक्ष के समर्थन में पेश किये गये :-

1- विक्रय पत्र दिनांक 31-8-84 की फोटो कापी।

2- भूमि अधिपति अधिकारी, सावजनिक निर्माण विभाग, वृत्त-2 जयपुर के आर्डर दिनांक 20-2-85 की फोटो कापी।

3- भूमि अधिपति अधिकारी, सावजनिक निर्माण विभाग, वृत्त-2 जयपुर के आर्डर दिनांक 4-2-86 की दो फोटो कापी।

11] उपरोक्त मामलों में दावेदारों द्वारा अपनी भूमि के मुआवजे हेतु भूमि की दर 300/- प्रति वर्ग गज बाद संख्या 10/83/94 ए में एवं 82,000/- रुपये बाद संख्या 10/83/94 बी में प्रतिबीघा दिये जाने की मांगी की है।

12] राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा अपने जवाब में यह उल्लिखित किया गया है कि इस कृषि भूमि की कीमत अधिक से अधिक रुपये 10,000/- प्रति बीघा हो सकती है, इससे अधिक कदापि नहीं एवं अपने इस कथन के समर्थन में उनके द्वारा विक्रय पत्र दिनांक 24-10-83 जिसमें ग्राम श्योपुर की 3 बीघा 3 बिस्वा भूमि रुपये 29,999/- में बेची गई है, की फोटो कापी पेश की है। जिसके अनुसार उक्त भूमि की दर 9,523/- प्रति बीघा है, किन्तु इस विक्रय पत्र का अध्ययन करने से यह तथ्य जानकारी में आता है कि एवं यह विक्रय पत्र ही उल्लिखित भी किया गया है।

यह भूमि खंबाला की नदी के पास स्थित है। विगत बाढ़ के समय आधी से ज्यादा जमीन नदी की चोट में आ जाने से खाले पड़े हुए है तथा आधी से अधिक जमीन नदी के रूप में है तथा शेष डेढ़ या पौने दो बीघा जमीन ही कार्य की है। उक्त भूमि पर किसी प्रकार की पैदावार नहीं

विशेषाधिकारी

नगरीय विकास एवं आवासन विभाग  
राजस्थान, जयपुर

इस प्रकार यह विक्रय पत्र की प्रति जो पेश की गई है उसमें विक्रय तो 3 बीघा 3 बिस्वा किया जाना बताया गया है लेकिन वास्तविक रूप में जमीन आधी या एक चौथाई ही विक्रय की गई है एवं चूंकि इस भूमि में किसी प्रकार की पैदावार नहीं की जाती है इसलिये इस विक्रय पत्र के आधार पर वर्तमान मामलों में भूमि की दर निश्चित किया जाना भरे विचार से न्यायोचित नहीं होगा।



राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में अन्य विषय पत्र दिनांक 19-3-84 की प्रति पेश की गई है जिसमें ग्राम बंबाला में 01 बीघा 01 बिस्वा भूमि का आधा हिस्सा रु 20,000/- में विप्रेत किया गया जिसके अनुसार भूमि की दर लगभग 7,500/- प्रति बीघा है। इस विप्रेत पत्र के अन्त में यह लिखा गया है कि 'विप्रेत की गई भूमि कस्बे से करीबन 3 किलोमीटर अन्दर क्षेत्र में है तथा भूमि किसी भी रोड लाइन पर नहीं है एवं भूमि खाली है।'

इस प्रकार इस विप्रेत पत्र के द्वारा कस्बे से 3 किलोमीटर अन्दर जाकर भूमि विप्रेत की गई है, अतः इस विप्रेत पत्र के आधार पर वर्तमान मामले में भूमि की दर तय किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में ग्राम बंबाला की 7 बीघा 18 बिस्वा भूमि का 1/3 हिस्सा दिनांक 30-5-83 को रुपये 25,000/- में विप्रेत किये जाने पर विप्रेत पत्र की फोटो प्रति पेश की है जिसके अनुसार भूमि की दर लगभग रु 9,500/- अती है। इस विप्रेत पत्र में यह नोट लिखा गया है कि विप्रेत पत्र की गई कृषि भूमि टोंकरोड से करीबन 1-1/2 मील अन्दर क्षेत्र में है इसलिए भेरे विचार में इस विप्रेत पत्र के आधार पर वर्तमान मामलों में भूमि की दर तय किया जाना न्यायोक्ति नहीं होगा।

राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा अपने उपरोक्त के अतिरिक्त अपने पक्ष के समर्थन में कोई अन्य सख्त या दस्तावेज पेश नहीं किया गया है।

13] सम्बन्धित दावेदारों द्वारा अपने क्लेम के समर्थन में विप्रेत पत्र दिनांक 31-8-84 की फोटो प्रति पेश की है जिसके अनुसार ग्राम बंबाला में 10 बिस्वा बंजर भूमि रुपये 47,999/- में विप्रेत की गई है इसके अनुसार भूमि की दर लगभग 96,000/- प्रति बीघा आती है।

14] इसके अतिरिक्त सम्बन्धित दावेदारों द्वारा न्यायालय भूमि अधिपति अधिकारी, सार्वजनिक निर्माण विभाग, वृत्त-2, जयपुर के आदेश दिनांक 20-2-85 की प्रतिलिपि पेश की गई है जिसके अनुसार ग्राम बंबाला में 01 बीघा 10 बिस्वा भूमि का मुआवजा 40,000/- रुपये प्रति बीघा की दर से तय किया गया है, किन्तु इस मामले में सार्वजनिक निर्माण विभाग को भूमि विशेष की ही आवश्यकता होने के कारण यह मुआवजा दिया गया है। अतः इस आदेश के आधार पर ही वर्तमान मामलों में भूमि की दर तय किया जाना भेरे विचार से न्यायोक्ति नहीं होगा।

15] इन प्रकरणों से सम्बन्धित मोके का निरीक्षण किया एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अध्ययन किया तथा सम्बन्धित पक्षकारों की बहस

विशेष अधिकारी  
राजस्थान आवासन विभाग  
जयपुर



43

उसी । यह भूमि जयपुर नगर के निकट सांगमर हाउस में स्थित है ।  
सांगमर हाउस में स्थित है । का। अधिष्ठाता ने होने वाले विकास  
के दृष्टिकोण से भूमि की स्थिति महत्वपूर्ण है । का। भूमि की  
पौष्टिकता के आधार पर एवं सांगमर हाउस के समीप होने के कारण  
एवं अधिष्ठाता ने होने वाले विकास के दृष्टिकोण से वाद संख्या 10/83/94  
में कुल 9 बीघा 10 बिस्वा मुख्य रुक पर स्थित है जिसकी भूमि की दर  
रुपये 26,000/- प्रतिबीघा की दर से दिया जाना न्यायोचित मानता है,  
एवं वाद संख्या 10/83/94 बी। में उसरा नं० 260/643 रक्बा । बीघा  
02 बिस्वा जो मुख्य रुक पर स्थित है एवं जिसकी दर 26,000/-  
रुपये प्रति बीघा एवं उसरा नं० 57 व 78 कुल रक्बा 3 बीघा 17 बिस्वा  
जो कि मुख्य रुक से दूरी पर स्थित है एवं जिसकी दर 24,000/-  
प्रति बीघा दिया जाना न्यायोचित मानता है ।

16। इन दोनों ही मामलों में राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा वाद संख्या  
10/83/94 बी। में कुल 9 पेड स्थित होने के कारण उनका मुआवजा  
रुपये 900/- दिया जाना न्यायोचित मानता है एवं इसी प्रकार वाद संख्या  
10/83/94 बी। में भी पेडों का तकमीना पेश नहीं किया गया है लेकिन  
मोका मुआवजा के समय मोके पर कुल 6 पेड होने के कारण उनका मुआवजा  
रुपये 750/- दिया जाना न्यायोचित मानता है ।

इसके अतिरिक्त राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा अपने तकमीने में  
डोले के मुआवजा नहीं दिया गया था लेकिन मोके पर भूमि के दोनों तरफ  
डोलीपाई गई जिसका मुआवजा राजस्थान आवासन मण्डल के अभियन्ता  
द्वारा रुपये 369.39/- काये गये जिसका दिया जाना न्यायोचित  
मानता है ।

विशेषाधिकारी  
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग  
राजस्थान, जयपुर

उपरोक्त अतिरिक्त दिनांक 8-7-86 को राजस्थान आवासन मण्डल  
के भूमि अधिष्ठाता अधिकारी श्री सत्येन्द्र शर्मा द्वारा एक प्रार्थनापत्र पेश कर  
यह निवेदन किया गया कि पूर्व में राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा उसरा नं०  
367 में पके निर्माणों का तकमीना पेश नहीं कर यह निवेदन  
किया गया था कि पके निर्माणों का कब्जा प्राप्त होने तक उनका मुआवजा  
स्वीकार नहीं है अब उनके द्वारा प्रार्थनापत्र पेश कर यह निवेदन किया गया  
कि पके निर्माण बाक्य भी मुआवजा इस आदेश में सम्मिलित कर दिया जावे  
इस हेतु उनके द्वारा तकमीना रुपये 10,428.42/- भी पेश किया गया ।



इस बाबद दावेदार के अधिका भी कमानलहाय के अनुसार नही है वरन् राज  
पेश किया गया कि इसके बाबद उन्हे कोई सुचना नही है एवं प्लान में जो  
राजस्थान आवातन मण्डल जो जवाब दिया गया है उसी के अनुसार जांच  
किया जाये । इस प्रकार जांच के समय पर जवाब में किना सुचना के  
राजस्थान आवातन मण्डल द्वारा त्रुटि का नियमानुसार नही है ।

दोनों पक्षों के सुनने के परचाव में इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि  
वर्तमान में पक्ष के निर्माण का एस्टीमेट आर्डर में शामिल करना न्यायोचित  
नहीं होगा ।

117 इन मामलों में दावेदारों के की वकील बख्त द्वारा वक्त बहस यह  
मार्ग की गई थी कि अनिवार्य आप्रति हेतु दिये जाने वाले सोलेशियम की  
दर 10% के स्थान पर केन्द्रीय सरकार द्वारा 30% कर दी गई है व ब्याज  
की दर 4% के स्थान पर 12% कर दी गई है तथा ब्याज कब्जे की दिनांक  
से दिये जाने के स्थान पर धारा 4(1) की विनियमित प्रकाशन की दिनांक से  
दे दिया गया है, अतः उनको भी निर्देशों के अनुसार सोलेशियम व ब्याज की  
राशि भी दी जावे । किन्तु केन्द्रीय सरकार के इन निर्देशों के बाबद  
इस न्यायालय को कोई जानकारी नही है एवं न ही राजस्थान सरकार  
द्वारा इस बाबद कोई निर्देश इस न्यायालय को प्राप्त हुए हैं अतः केन्द्र  
नियमानुसार सोलेशियम 10% व ब्याज 4% दिया जाता है तथा यदि राज्य  
सरकार द्वारा इस बाबद भविष्य में निर्देश दिये जाते हैं तो उन निर्देशों  
के अनुसार इन मामलों में कार्यवाही की जा सकती है ।

118 उपरोक्त विवेचन के आधार पर दावेदारों के हक में मुआवजे का  
निर्धारण नियमानुसार किया जाता है :-

11 वाद संख्या 10/83/945 श्रीया, पारिया एवं रामदेव :-

|                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| अ) भूमि खसरा नं० 367, 369, 370, 371, 372, 374, 375, 376, 381 कुल<br>रकबा 5 बीघा 10 बिस्वाभूमि का मुआवजा रुपये 26,000/- प्रतिबीघा<br>की दर से रुपये 1,43,000.00 /- |
| कुवा व अन्य निर्माण का राजस्थान आवातन<br>मण्डल द्वारा प्रस्तुत तकमीने रुपये 25,352.10 /-                                                                          |
| पेड़ों का मुआवजा 900.00 /-                                                                                                                                        |
| डोले का मुआवजा 369.39 /-                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                   |
| 1,69,621.49 /-                                                                                                                                                    |
| ब) अनिवार्य आप्रति का मुआवजा 10%<br>की दर से 16,962.14 /-                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                   |
| 1,86,583.63 /-                                                                                                                                                    |
| ग) मुआवजे की राशि पर 4% वार्षिक की दर<br>से साधारण ब्याज 11-6-84 से 9-7-86 तक 15,499.22 /-                                                                        |
|                                                                                                                                                                   |
| 2,02,082.85 /-                                                                                                                                                    |

विशेषाधिकारी  
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग  
राजस्थान, जयपुर



35

कुल रकम का आधा हिस्सा बीधा पुन समेत रु 1,01,641.42

एवं आधा हिस्सा बाँटा पुन समेत रु 1,01,641.42

[2] बाँट लिया 10/82/94 बी. श्री रामनाथ पुन समेत



[अ] भूमि खतरा नं 260/643 रकम 1 बीधा 02 बिघा 1 कच पर स्थित लिखित भूमि का मुआवजा रुपये 26,000/- प्रति बीधा की दर से :- रुपये 28,600.00

खतरा नं 57 व 78 कुल रकम 3 बीधा

17 बिघा का मुआवजा रु 24,000/-

प्रतिबीधा की दर से रुपये :-

रुपये 92,400.00

1,21,000.00

पेडों का मुआवजा रुपये

750.00

1,21,750.00

[ब] वनिवार्य व्याप्ति का मुआवजा 10% की दर से रुपये

12,175.00

1,33,925.00

[स] मुआवजे की राशि पर 4% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज दिनांक

11-6-84 से 9-7-86 तक रुपये

11,124.95

कुल

1,45,049.95

इस प्रकार आज दिनांक 9-7-86 को कुल 3,47,132.80 रुपये और तीन लाख सैतालीस हजार एक सौ बत्तीस रुपये अस्सी पैसे मात्र का ब्याज घोषित किया गया। अधिनियम की धारा 12(1) के अनुसार ब्याज सभी पत्रावलियों में शामिल फाईल हो एवं धारा 12(2) के अनुसार सम्बन्धित दावेदारान को सूचित किया जावे तथा प्रतिलिपि शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान, जयपुर, ~~सचिव~~ सचिव, राजस्थान आवासन मंडल, जयपुर एवं तहसीलदार सांगानेर को प्रेषित हो। ब्याज से इजलास सुनाया गया।

विशेषाधिकारी,

नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राज. जयपुर।

O/c

क्रमांक:- 1589

दिनांक:- 9-7-86

प्रतिलिपि निम्न को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही के लिए प्रेषित है:-

[1] श्रीमान् शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राज. जयपुर

[2] श्रीमान् आवासन अधिकारी, राजस्थान आवासन मंडल, जयपुर।

[3] सचिव, राजस्थान आवासन मंडल, जयपुर।

[4] तहसीलदार, सांगानेर, जिला जयपुर।

[सम्बन्धित आवेदक/विधायी श्री रामनाथ पुन अध्येत]

O/c

विशेषाधिकारी,

नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राज. जयपुर।